International Journal of Advanced Education and Research
www.multidisciplinaryjournals.net
ISSN: 2455-5746
Received: 18-02-2023, Accepted: 07-03-2023, Published: 22-03-2023
Volume 8, Issue 1, 2023, Page No. 63-64

भावी उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ में एनईपी 2020 की एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि

संध्या यादव
शोध छात्रा, जे. एस. यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
यह शोध पत्र नई शिक्षा नीति 2020 के लिए संदर्भित है। नई शिक्षा नीति (NEP)का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर शैक्षिक रूप से महाशक्ति बनाना तथा भारत में शिक्षा का सार्वभौम करण कर शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शुभारंभ से भारतीय उच्च शिक्षा में एक नए युग की शुरुआत होगी, जो पहले से काफी बेहतर होगा और एक नये भविष्य का निर्माण करेगा। एनईपी 2020 एक उत्कृष्ट दूरदृष्टि का परिणाम है और एक प्रेरणादायक नीति दस्तावेज है जो भारतीय उच्च शिक्षा के परिदृश्य में एक मूलभूत परिवर्तन का आगाज करेगा। इसके तहत भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली की जटिलता और चुनौतियों को ईमानदारी और स्पष्टता के साथ पहचाना गया है। इसके तहत मानव विकास की असाधारण क्षमता और जनसांख्यिकी लाभांश का उपयोग करने के लिए एक व्यापक बदलाव लाने के लिए एक दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है, जो कि भारत जैसे देश में बहुतायत में उपलब्ध है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ने और विकसित होने के लिए एक समान अवसर प्रदान करता है तथा विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल, बुद्धि और आत्मविश्वास का सृजन कर उनके दृष्टिकोणों का विकास करता है उपयुक्त विश्लेषित तथ्यों के आधार पर शोधकर्ता इस शोध पत्र के माध्यम से अनेक सुझावों को प्रस्तुत करता है जो भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए अति आवश्यक है।

मूल शब्द: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षार्थी, उच्य शिक्षा

प्रस्तावना
आदिकाल से भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयास किए गए उनका श्रेय तत्कालीन धर्माचारों मनीषियों एवं ऋषि–मुनियों को जाता है उनके द्वारा रचित संयोजित जो भी ज्ञान संपदा है वह विरासत में मिली है ज्ञान के एक वृहद भाग का विकास भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा अपने आश्रमों में गुरुकुलओं परिषदों तथा विद्यापीठो में किया गया वैदिक काल से ही संस्कृत भाषा इस ज्ञान संग्रह का माध्यम रही है प्राचीन काल में उचित शिक्षा का स्वरूप आज ऐसा नहीं था प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा की व्यवस्था आधुनिक काल की देन है। भारत में शिक्षा का इतिहास काफी पुराना है। जब विश्व के तथाकथित विकसित देशों का नामों निशान भी नहीं था, तब से हमारे यहां वेदों जैसे गूढ़ ग्रन्थों का स्वरूप प्राप्त हो चुका था। जिनके अन्दर निहित समस्त ज्ञान विज्ञान को आज भी उद्घाटित नहीं किया जा सका है अर्थात् भारत में शिक्षा विदेशियों की देन नहीं है वरन् भारत शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं में काफी समृद्ध रहा है। डॉ. एफ. डब्ल्यू. थामस (1955) के शब्दों में" भारत में शिक्षा का कोई विदेशी पौधा नहीं है, संसार का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ ज्ञान के प्रति प्रेम का इतने प्राचीन समय में अविर्भाव हुआ हो या जिसने इतना चिरस्थायी और शक्तिशाली प्रभाव डाला हो।"
भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं मे से एक है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय सभ्यता उस समय भी विश्व की अन्य सभ्यताओं से उन्नत एवं समृद्ध थी। निश्चय ही तत्कालीन समृद्धि के मूल में शिक्षा का योगदान अवश्य रहा होगा, क्योंकि शिक्षा और समाज तो एक दूसरे पर आश्रित हैं। यद्यपि भारत में शिक्षा का बीजारोपण सुदूर अतीत में आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व हुआ था। उसके सुसम्बद्ध स्वरूप के दर्शन, वैदिक काल के आरम्भ से होते हैं। इसका मूल कारण शायद तत्कालीन शिक्षा पद्धति का मौखिक स्वरूप था, क्योंकि भारतीय लिपि पद्धति का विकास काफी बाद में हुआ और उसके बाद ग्रन्थों को लिपिबद्ध किया गया। इससे पूर्व का समस्त साहित्य मौखिक रूप से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित किया गया और समृद्ध होता रहा। भारत के इतिहास से स्पष्ट होता है कि भारत का राजनैतिक परिदृश्य काफी उतार चढ़ाव का रहा है। जिसने भारत की सामाजिक व्यवस्था पर भी अपना प्रभाव डाला। जिसकी वजह से भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भी समय के अनुसार अनेकानेक परिवर्तन हुए तथा शिक्षा का प्रसार अनवरत रूप से जारी रहा।

भारत मे उच्च शिक्षा प्रणाली
हमारे देश भारत की सरल शिक्षा प्रणाली (मकनबंजपवद पद पदकपं) की शुरुआत आजादी के साथ ही हुई थी। पिछले 7 दशकों में भारत ने प्राथमिक, माध्यमिक, कॉलेज, उच्च शिक्षा, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है।फिर भी देश में उच्च शिक्षा की कई बातें सच हो जाती हैं तो लाखों छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश न जाना पड़े। भारत में उच्च शिक्षा के इस लेख में हम जानेगे कि उच्च शिक्षा का अर्थ नवाचार प्रणाली का विरोध, निजीकरण गुणवत्ता की अव्यवस्था की स्थिति आदि के बारे में इस आलोचना में जानेगे। गिरने के समान उच्च शिक्षा को और निश्चित एवं परिमार्जित करने के उद्देश्य से शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह घोषणा की गई थी। इस नई नीति के तहत पूरे देश में शिक्षा को एक समान अर्थात 10+2+3 के शैक्षिक ढांचे की शुरुआत हुई थी। इस समय पूरे देश में इसी शैक्षणिक व्यवस्था की व्यवस्था है। इसे प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में विभाजित किया जा सकता है। भारत सदियों से विदेशियों की अक्षमता परतंत्रता के इस दौर में भारतीय शिक्षण संस्थान लगभग समाप्ति की दहलीज पर थे, ऐसे में देशी विदेशी लोगों के प्रयासों से ब्रिटिश काल में आधुनिक शिक्षा की नीव पड़ी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में इसमें सुधार करते हुए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास शुरू किया गया। सन 1948 में उद्देश्य की व्याख्या सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध् यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। इसके बाद से उच्च शिक्षा की समीक्षा एवं इसमें सुधार के लिए समय–समय पर कई शिक्षा आयोगों का गठन किया जा रहा है। आज भारत में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले कुछ विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थान हैं। विदेशी छात्र भी भारत में अब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने वाले हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020, की उच्च शिक्षा में मुख्य, बिंदु

NEP 2020 भारत में 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। स्वतंत्रता के बाद यह भारत की केवल तीसरी शिक्षा नीति है। शिक्षा के लिए पहली नीति 1968 में प्रख्यापित की गई थी और दूसरी 1986 में लागू की गई थी। NEP 2020 का लक्ष्य 2040 तक एक कुशल शिक्षा प्रणाली बनाना है, जिसमें सभी शिक्षार्थियों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान पहुंच हो। इसका उद्देश्य एक नई प्रणाली का निर्माण करना है जो भारत की परंपराओं और मूल्य प्रणालियों पर निर्माण करते हुए SDG 4 सहित 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षात्मक लक्ष्यों के साथ संरेखित हो। यह राज्यों, केंद्र द्वारा शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च को जीडीपी के 6% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित करता है। NEP 2020 का उद्देश्य 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% करना है। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) का उद्देश्य बहु–विषयक संस्थान बनना होगा, जिनमें से प्रत्येक में 3,000 या अधिक छात्र होंगे।

NEP 2020 के मुख्य बिंदु

- उच्च शिक्षा
- विषयों के ढील के साथ शिक्षा के प्रति एक समग्र और बहुआयामी दृष्टिकोण
- UG प्रोग्राम में एकाधिक बार प्रवेश/निकास। उदाहरण के लिए, व्यावसायिक और व्यावसायिक क्षेत्रों सहित एक अनुशासन में 1 वर्ष पूरा करने के बाद एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, 2 साल के अध्ययन के बाद एक डिप्लोमा और 3 साल के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी।
- 4–वर्षीय बहु–विषयक बैचलर प्रोग्राम वैकल्पिक होगा।
- यदि छात्र 4–वर्षीय प्रोग्राम में एक बड़ा अनुसंधान परियोजना पूरी करता है, तो उसे 'रिसर्च' की डिग्री दी जाएगी।
- M-Phil को बंद किया जाएगा।
- एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो एक छात्र द्वारा अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत करेगा।
- Research/Teaching Intensive विश्वविद्यालयों की स्थापना
- भारत के परिसर में विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना
- हर शैक्षणिक संस्थान में, छात्रों के टेंशन और इमोशन को संभालने के लिए परामर्श प्रणाली होगी।
- कई प्रवेश और निकास विकल्पों के साथ चार वर्षीय स्नातक डिग्री शुरू की जाएगी।
- एम.फिल की डिग्री समाप्त कर दी जाएगी।
- चिकित्सा, कानूनी पाठ्यक्रमों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षा के लिए नया अम्ब्रेला नियामक।
- संस्थानों के बीच हस्तांतरण को आसान बनाने के लिए एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी।
- कॉलेज संबद्धता प्रणाली को 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा, ताकि प्रत्येक कॉलेज या तो एक स्वायत्त डिग्री देने वाली संस्था या किसी विश्वविद्यालय के एक घटक कॉलेज के रूप में विकसित हो सके।

इसका उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2018 में 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना है, जिसमें अतिरिक्त 3.5 करोड़ नई सीटें हैं।

भारत में वर्तमान में 1,000 से अधिक उच्च शिक्षण संस्थान (HEI) मौजूद हैं, जिनमें राष्ट्रीय महत्त्व के 150 से अधिक संस्थान शामिल हैं। समय के साथ ये वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र भी बन गए हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों ने पिछले दशक में शोधों की संख्या और उनकी गुणवत्ता दोनों में ही लगातार वृद्धि प्रदर्शित की है। वर्तमान में भारत कुल शोध प्रकाशनों के मामले में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है और कुल शोध प्रकाशनों में इसकी हिस्सेदारी 5.31 प्रतिशत है। शिक्षा, ज्ञान सृजन (अनुसंधान एवं विकास) और नवाचारकृइन तीन पहलुओं में से पहले दो पहलुओं में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों ने सापेक्षिक रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन नवाचार के मामले में वे पीछे रहे हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy& NEP) से अपेक्षित है कि यह उच्च शिक्षा संस्थानों को" समस्या की तलाश में समाधान" के बजाय "समस्याओं के समाधान" पर कार्य करने लिये प्रेरित कर भारत में उच्च शिक्षा के परिदृश्य को रूपांतरित कर देगा

उपसंहार

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 एक अच्छी नीति है क्योंकि यह शिक्षा प्रणाली को समग्र, लचीला, बहु–विषयक और 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने पर लक्षित है। नीति की मंशा कई मायनों में आदर्श प्रतीत होती है, लेकिन निश्चय ही इसकी सफलता इसके कुशल कार्यान्वयन पर निर्भर होगी।

अंत में संपूर्ण प्रपत्र के अध्ययन करने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा रटने वाली विषयों समय सीमा को पूरा करने और अंक प्राप्त करने से कहीं अधिक है। लेकिन शिक्षा का वास्तविक अर्थ ज्ञान कौशल मूल्यों को प्राप्त करना और उस क्षेत्र में निरंतर कार्य करना और प्रगति करना है जिसमें व्यक्ति अपनी रूचि खोज की सकता है ।इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर अपनी शिक्षा नीति 2020 को सही तरीके से लागू किया जाए तो यह भारतीय शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। हालांकि इसके कुछ देशों में लक्ष्यों की स्पष्टता का अभाव है लेकिन इस हम वास्तव में इसका न्याय तब तक नहीं कर सकते जब तक कि इसकी लिखित योजना क्रिया में ना आ जाए हम केवल सर्वोत्तम परिणामों की आशा कर सकते हैं आखिरकार के छात्रों के समग्र विकास और प्रगति को ध्यान में रखते हुए लाई गई है।

संदर्भ सूची

1. https%@@www-education-gov-in@upload files@mhrd@files@NEP final English o-pdf
2. https%en-wikipedia-org@wiki@national education policy 2020
3. भारत, शिक्षा 1988–89 प्रकाशन विभाग सूचना एवम प्रसारण भारत सरकार नई दिल्ली
4. 4&http%@@s3&ap&southeast&1-amazonaws-com@ijmer@pdf@volume10@volume10&issue2¼@33-pdf
5. https%@@innovate-mygov-in@wpcontent@uploads@2019@06@mygov15596510111-pdf new education policy 2020